

प्रकाशनाथ

रिपोर्ट का लोकार्पण पटना शहर के लिए व्यापक स्वच्छ वायु कार्ययोजना

पटना, 23 नवंबर, 2019 : आज 23 नवंबर, 2019 को बिहार के माननीय उप-मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा पटना स्वच्छ वायु कार्ययोजना (पीसीएएपी) का लोकार्पण किया गया। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अपनाई गई कार्ययोजना को सीस्टेप (सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी) और अर्बन एमिशन द्वारा विकसित किया गया है। लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन आद्री स्थित सेंटर फॉर एनवायरनमेंट, एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज (सीईईसीसी, आद्री) द्वारा किया गया। यह पहल ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रॉपीज और शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन (एसएसईएफ) द्वारा समर्थित है।

पटना केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा चिन्हित 122 नॉन-अटेनमेंट शहरों में से एक है। पटना स्वच्छ वायु कार्ययोजना को मुख्य प्रदूषक क्षेत्रों और उन क्षेत्रों में प्रदूषण रोकने के लिए नियंत्रक उपायों पर सघन अनुसंधान के बाद तैयार किया गया है। पटना देश का पहला ऐसा शहर है जिसने शोध समूहों द्वारा अपनाई गई वैज्ञानिक प्रविधि के आधार पर व्यापक योजना का शुभारंभ किया है। अध्ययन का आकलन है कि 2030 तक सामान्य कार्यस्थितियों (बीएयू) में पटना में पीएम2.5 के उत्सर्जन का कुल लोड लगभग 28,000 टन प्रति वर्ष होगा (जो आधार वर्ष 2018 में 20,000 टन प्रति वर्ष था)। परिवहन, घरेलू और औद्योगिक क्षेत्रों को 2030 में पीएम2.5 के उत्सर्जन के कुल लोड में योगदान करने वाले प्रदूषण के मुख्य स्रोतों के बतौर चिन्हित किया गया है। पटना में प्रदूषण के संकेंद्रण के वार्षिक औसत में सर्वाधिक 23 प्रतिशत बाहरी स्रोतों का, 21 प्रतिशत (खाना पकाना, गर्म करना और प्रकाश व्यवस्था सहित) घरेलू क्षेत्र का, और 19 प्रतिशत परिवहन क्षेत्र का योगदान होने का अनुमान है। इनके अलावा, पूरे प्रदूषण में उद्योगों का 12 प्रतिशत, खुले में कूड़ा जलाने का 11 प्रतिशत, धूल का 11 प्रतिशत, और डीजल जेनरेटर सेटों का 4 प्रतिशत योगदान होना अनुमानित है।

अपने मुख्य संबोधन में बिहार सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार सिंह ने कहा कि बिहार सरकार राज्य के सभी बड़े शहरों में हवा की गुणवत्ता के प्रबंधन के मामले में बहुत सक्रिय है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन पर कार्ययोजना होने से हमें कुछ गंभीर वैज्ञानिक कार्रवाइयां करने में मदद मिलेगी।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार के उप-मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में बिहार में वायु प्रदूषण में योगदान करने वाले मुख्य कारकों का उल्लेख किया। उन्होंने जानकारी दी कि प्रदूषण बढ़ाने वाले कारकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करते हुए बिहार सरकार ने पटना में 15 वर्ष से पुराने वाहनों का चलना प्रतिबंधित कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि पुराने वाहनों के प्रबंधन के लिए नई स्क्रेपिंग नीति की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार 2020 तक स्वच्छ इंधन प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए तिपहियों को 40,000 रु. सब्सिडी दे रही है। साथ ही, पटना में प्रदूषण जांच केंद्रों तक पहुंचना आसान बनाने के लिहाज से प्रदूषण जांच केंद्र चलाने के मापदंडों को आसान बनाकर अधिक संख्या में प्रदूषण जांच केंद्र उपलब्ध कराए गए हैं। पथ कर में कमी लाकर और चार्जिंग केंद्रों की संख्या बढ़ाकर बिजली से चलने वाले वाहनों को भी बढ़ावा दिया गया है। विद्युतचालित वाहनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री द्वारा विद्युतचालित कारों का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने विशेषज्ञों से अनुरोध किया कि वे सरकार को हर वर्ष वायु गुणवत्ता संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। वायु प्रदूषण पर व्यापक जनजागृति के लिए उन्होंने अनुरोध किया कि सभी मीडिया हाउस अपने दैनिक समाचार-पत्र का एक हिस्सा शहर में वायु गुणवत्ता की स्थिति के लिए समर्पित रखें। अंत में उप मुख्यमंत्री ने सीईईसीसी आद्री तथा अन्य सहयोगी संस्थाओं को एक्शन प्लान बनाने के लिए धन्यवाद दिया।

अपने विशेष संबोधन में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर अशोक कुमार घोष ने मानव स्वास्थ्य और सुख-सुविधा के विभिन्न पक्षों पर वायु प्रदूषण के गंभीर प्रभाव को रेखांकित किया। उन्होंने कार्ययोजना की प्रासंगिकता और कार्ययोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू) के गठन पर भी अपने विचार रखे।

अध्ययन की प्रधान रही सीस्टेप की शोध वैज्ञानिक डॉ. प्रतिमा सिंह ने विभिन्न प्रदूषक क्षेत्रों के लिए विभिन्न नियंत्रक उपायों की जानकारी दी। “हमने प्रौद्योगिकियों और उनके क्रियान्वयन व्यय की तुलना की। इससे हमें प्रदूषण घटाने और जीवन बचाने की सर्वोत्तम संभावना वाले उपायों की पहचान करने में मदद मिली। हमारा अनुमान है कि सर्वोत्तम स्थिति वाले परिदृश्य में 2030 तक पटना शहर के प्रदूषण में 69 प्रतिशत तक कमी आ पाना संभव होगा।”

अध्ययन के अनुसार, सार्वजनिक परिवहन में बिजली और सीएनजी से चलने वाले वाहनों का हिस्सा 40 प्रतिशत तक बढ़ाने से परिवहन क्षेत्र के प्रदूषण में 10 प्रतिशत कमी आ सकेगी। वहीं, टोस अपशिष्ट प्रबंधन की उचित सुविधा सुनिश्चित करके और कूड़ा जलाने पर कठोर नियमों को लागू करके कूड़ा जलाने से होने वाला उत्सर्जन 90 प्रतिशत तक घटाया जा सकेगा। और फिक्स्ड चिमनी वाले ईट भट्टों का जिगजैग किलन में परिवर्तन सुनिश्चित करने से ईट भट्टा क्षेत्र से होने वाला उत्सर्जन 34 प्रतिशत घटाने में मदद मिलेगी।



(अंजनी कुमार वर्मा)